

सम्पादकीय

टीबी का उन्मूलन

तपेदिक यानी टीबी एक गंभीर वैशिक बीमारी है। अनुमान है कि दुनिया की एक-तिहाई आबादी टीबी के बैकिटरिया से संक्रमित है, जिसमें केवल पांच से पंद्रह फीसदी लोग ही बीमार पड़ते हैं। शेष संक्रमितों को न तो टीबी की बीमारी होती है और न ही उनके जरिये यह संक्रमण दूसरों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2020 में दुनियाभर में लगभग एक करोड़ लोग तपेदिक के शिकार हुए थे और 15 लाख लोगों की मौत हो गयी थी। साल 2019 में भारत में 24 लाख से अधिक मरीजों की तादाद दर्ज की गयी थी। इस हिसाब से देखें, तो भारत में टीबी के सर्वाधिक रोगी हैं। बीमार व्यक्ति से इसका संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। इस बीमारी से मुक्ति के प्रयास वर्षों से हो रहे हैं।

भारत अभियान' की शुरुआत की है। इसके तहत 2025 तक देश को टीबी से पूरी तरह छुटकारा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए इसमें शामिल होने के लिए पूरे देश का आवान किया है। उन्होंने कहा है कि जब जनहित में कोई कल्याणकारी योजना बनायी जाती है, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। टीबी और इसके निदान से संबंधित जानकारी देने के लिए एक विशेष वेबसाइट 'नि-क्षय मित्र' बनायी गयी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों, उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नागरिकों से निवेदन किया है कि वे इस पहल में दान करें ताकि रोगियों को सफल उपचार मुहैया कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि 2017 में एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गयी थी, जिसके तहत 2025 तक इस खतरनाक बीमारी से मुक्ति का लक्ष्य तय किया गया था। इस प्रयास में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को भी सशक्त बनाया गया है। अनेक दर्शकों की कोशिशों तथा हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिये जाने से इस मोर्चे पर लगातार उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

जेराव्य होता है और इतना उपयोग रखने होता है। ताकि आवश्यकता में उपयोग ही रखांकित किया है कि इसके बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। कई बार लोग टीबी के लक्षणों को सामान्य स्वास्थ्य समस्या मानकर उनकी अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने और फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी अनेक पहलों से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नीतियों और योजनाओं के केंद्र में नागरिकों को रखने से इनका प्रभाव भी संतोषजनक है। आशा है कि हमारा देश कुछ वर्षों में तपेदिक के साथ से बाहर निकल जायेगा।

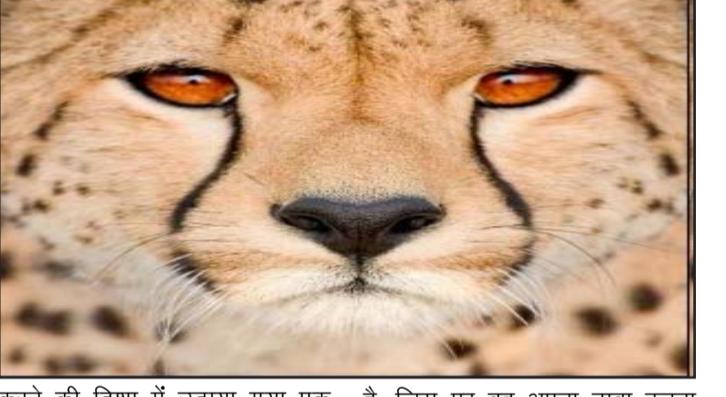
मारे देश में चीते की वापसी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत एक बार फिर से जमीन के नबसे तेज जानवर का स्वयंगत करने वाला बेताबी से इंतजार कर रहा है,



A black and white photograph capturing a moment of interaction or speech. In the foreground, a man with dark hair and a beard is gesturing with his hands while speaking. He is wearing a light-colored shirt. Behind him, another man in a white shirt is smiling broadly. In the background, there are other people, some partially visible, and a flag, possibly the Indian national flag, is visible. The setting appears to be outdoors, possibly during a political event or rally.

तो कहते हैं कि लोगों की जेब में डालो, उन्हें काम दो अर्थव्यवस्था पहिया घूमना फिर से शुरू हो गया। आज रुक गया है। दो के बावा किसी भी उद्योगपति से पूछ बै बताएंगे कि गांवों, छोटे शहरों में वह आदमी के उपयोग के लिए जो गान जाता था उस सबकी बिक्री हो गई है। लोगों के पास पैसा ही है। जब 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई थी तो गांवों में सबसे पहले टर, मोटर साइकिलें पहुंचना शुरू ही। फिर क्रिज गया। और 2004 बाद ऐसी, वाशिंग मशीनें, कार बने लगीं। आज जाकर देखिए तो का दुकानदार कहेगा कि टूथ पेस्ट, शैम्पू रखना अब बंद कर दूँ। कहां शैविंग क्रीम तक मिल गा था हैरत है कि आज अर्थव्यवस्था बढ़ाने के बदले ऐसी बातें की जा हैं जैसी 70-75 साल पहले की थीं। उन दिनों रेडियो, अखबार, कै जैते पारकर का पेन काटन पर पहले ही जीएसटी लग चुकी है। आटा महंगा, चावल महंगा और चर्चा करेंगे शर्ट की कीमत पर। करो! और राहुल आप इससे भी महंगी टी शर्ट पहनो। गांधी का मैसेज हो गया। तब उसकी जरूरत थी। कपास यहां से जाता था। कपड़ा वहां से बनकर आता था। उनका कपड़ा कम उपयोग करने के लिए गांधी ने लंगोटी लगा ली। मगर आज जरूरत आंबेडकर के संदेश की है। सूट में डॉ। आंबेडकर की तस्वीर याद कीजिए। राहुल की तरह अपने पैसों का खरीद कर पहनते थे। मैसेज यह था कि देश का गरीब, दलित, पिछड़ा सब अच्छे कपड़े पहनें। कपड़ों के आधार पर कोई कमजोर, निर्धन नहीं दिखे। राहुल का संदेश इससे थोड़े से आगे का है। कांग्रेस ने नेहरू के समय से ही सरकारी नौकरियां देकर एक नया मध्यमवर्ग बनाया। 1991 में खुली अर्थव्यवस्था के तहत रोजगार के नए मौके मुहैया करवाकर उसका और विस्तार किया और फिर 2004 में उसे गांव-गांव तक पहुंचा दिया। राहुल की न्यायोजना इससे आगे की थी। 2019 चुनाव से पहले उन्होंने इसका ऐलान किया था। राहुल के शब्दों में गरीब जेब तक पैसे पहुंचाना। देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता की यह योजना थी। दुनिया भर के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस मनरेगा की तरह ही क्रान्तिकारी योजना बताया था। जो गरीबों की आर्थिक स्थिति भी सुधारती और देश की भी यह पैसा जब गरीब के पास पहुंचता है तब वह चलता है। घूमता है। मार्केट उसे से बनता है। वही गरीब का लड़का-लड़की जीन्स, टी शर्ट, टॉप पहनता है। उसमें स्मार्टनेस आती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा और पहनावे से ही वह दूसरों के मुकाबले खड़ा होता है।—**शक्तीन अख्तर**

फिर लाटगा चाता



करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। 'मिशन लाइफ' का उद्देश्य वास्तव में एक ऐसी समावेशी दुनिया का निर्माण करना है, जहाँ मनुष्य का लालच हमारी वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के अस्तित्व की जरूरत को नहीं लांघता, अपितु जहाँ मनुष्य जीव-जंतुओं सहित प्रकृति के साथ सद्भाव से रहते हैं। विकास के पश्चिमी मॉडल ने इस धारणा को जन्म दिया कि मानव सर्वोच्च है और प्रौद्योगिकी की शक्ति से युक्त यह सर्वोच्च मानव हर उस चीज को हासिल कर सकता है, जिस पर वह अपना दावा करता है। जब इस मॉडल को व्यवहार में लाया गया, तो मानव कहीं खो गये और इसके साथ ही उनके द्वारा अस्थायी रूप से अर्जित की गयी समृद्धि की भावना भी गुम हो गयी। इस मॉडल ने न केवल अनेक प्रजातियों को खतरे में डाला, बल्कि पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। युगों से भारत में हम 'प्रकृति रक्षणी' पर विश्वास करते आये हैं। हमारी आजादी के बाद से देश ने केवल एक विशाल जंगली स्तनधारी को खोया

कास संबंधी जरूरतों के बावजूद य, शेर, एशियाई हाथी, घड़ियाल एवं एक सींग वाले गैंडे सहित कई अत्यधिक प्रजातियों व उनके प्रारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने के सक्षम रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलीफेंट के साथ इन दो महत्वपूर्ण प्रजातियों की तादाद बढ़ाने में भी समर्थ रहा है। जहां एक बाघ वन प्रणालियों की एक प्रमुख वर्षीय प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता वर्हीं चीता खुले जंगलों, घास के बहावों और चारागाहों के शून्य को भर गया। चीते की वापसी धरती के टिकाऊ विवरण के निर्माण की दिशा में एक त्वाकांक्षी कदम है, क्योंकि एक शीर्ष भक्षी की वापसी ऐतिहासिक ग्रासवादी संतुलन को बहाल करती जो उनके पर्यावास की बहाली और कार के आधार के संरक्षण पर व्यापक दाव डालती है। चीता उस ग्रासवादी स्वभाविक चयन प्रक्रिया हिस्सा रहा है, जिसके कारण हिरण्य र चिंकारा जैसी प्रजातियों में उच्च वापसी लुप्तप्राय प्रजातियों और खुले वन पारिस्थितिकी तंत्र सहित उसके शिकार—आधार की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, जो कुछ हिस्सों में विलुप्त होने के कागार पर पहुंच चुकी हैं। प्रोजेक्ट चीता उपेक्षित पर्यावासों को बहाल करने के लिए संसाधन लायेगा, जिससे उनकी जैव विविधता का संरक्षण होगा, उनके पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और कार्बन को जब्त करने की उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग हो सकेगा। स्थानीय समुदाय को भी बड़े पैमाने पर जाभ होगा, क्योंकि चीते के लिए जिज्ञासा और सरोकारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न पारिस्थितिक तंत्र से उनकी आजीविका के विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा और उनके रहन—सहन की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। आज पूरी दुनिया विशाल मांसाहारी पशुओं और उनके पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो चुकी है। विशाल मांसाहारी पशुओं की संख्या में हो रही गिरावट के क्रम को रोकने या उलटने के लिए दुनियाभर

नांतरण का उपयोग किया जा रहा चूंकि ग्रह के संरक्षक के रूप में त अपनी आने वाली पीढ़ियों के टिकाऊ भविष्य का निर्माण करने अपने वादे को पूरा करने के लिए दिल से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ने भी चीते की वापसी का विकल्प नहीं, ताकि वह शीर्ष परभक्षी के में चीते की वापसी के साथ उसके परिस्थितिकी तंत्र की गिरावट का रुख ट सके। यूं तो चीते की पुनरु सी कुनों में हो रही है, लेकिन की तादाद में संभावित वृद्धि होने चीते को गुजरात, राजस्थान, रिटक और आंध्र प्रदेश सहित अन्य यों में प्रवेश कराया जा सकता है। ऐसे वन्यजीवन के अन्य रूपों और वृद्ध परिस्थितिकी तंत्र की बहाली साथ-साथ भारत की खोयी हुई ग्रासत को पूरी तरह बहाल करने में द करेगी।—**भूपेंद्र यादव**

प्रचार
अमेरि

हर तरह के प्रवचन
का मैं गन लौबी उ

भारत जाड़ा यात्रा और भारत का विचार



के लिए संघर्ष के लिए जमीन तैयार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यायद इसलिए अनेक सामाजिक समूह भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य बंधुत्व को बढ़ावा देना और आम लोगों की जिन्दगी की परेशानियों के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित करना है। आर्थिक असमानता बढ़ती ही जा रही है और समाज के एक बड़े तबके के नागरिक अधिकार केवल कागज पर रह गए हैं। बिलकिस बानो प्रकरण से पता चलता है कि समाज की सामूहिक सोच कितनी बदल गई है। भारत में यात्राओं ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। यात्रा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय थी। इस यात्रा ने आजादी हासिल करने के भारत के संकल्प को मजबूत किया और सामाजिक सुधार और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा को बलवती किया। आश्चर्य नहीं कि सांप्रदायिक संगठन इस यात्रा से दूर रहे। इस यात्रा का आयोजन इस तरह से किया गया कि देश के नागरिक धर्म और जाति की सीमाओं के ऊपर उठकर अपनी पहचान को भारतीय पहचान में समाहित करें। अम्बेडकर के महाड तालाब और कालाराम मंदिर आंदोलनों, जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना थी, के बाद गांधीजी ने जनता और असत्ता पर्याप्त के

विट्ठि सरकार के विरुद्ध अपने गान्दोलन को विराम देते हुए, 1933 के बाद से अनेक यात्राएं निकालीं। उनका उद्देश्य जातिगत पदक्रम और अचूत प्रथा का उन्मूलन था। इन यात्राओं से भी भारत को एक करने में दद मिली। इनके अतिरिक्त जगन्नाथ रेणू ने चुनावी लाभ के लिए, नटीआर ने सत्ता हासिल करने के लिए और चंद्रशेखर ने मुख्यतरु भारत को एक करने के उद्देश्य से यात्राएं निकालीं। परन्तु जिस यात्रा ने भारत को सबसे ज्यादा विभाजित किया वह भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथयात्रा। इस यात्रा को मंडल आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के सरकार के निर्णय परिप्रेक्ष्य में निकाला गया था। आडवाणी की यात्रा का एक लक्ष्य देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने था। इसके नतीजे में सांप्रदायिक इंडो बढ़ी और अंततरु बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। पिछले आठ वर्षों विघ्टनकारी राजनीति का बोलबाला जी से बढ़ा है और देश की एकता और बंधुत्व के भाव पर गंभीर कारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि भारत कोडो यात्रा एक राजनीतिक दल द्वारा निकाली जा रही है तथापि राष्ट्रीय कात्काता के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक संगठन उससे बुड़ रहे हैं। यहां तक कि ऐसे संगठन जो इसका समर्थन कर रहे हैं जो कई

